

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

भारत के आदिवासी समुदाय, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत हैं, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, इन समुदायों के कई व्यक्ति जानकारों के अभाव में सिकल सेल नामक अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे हैं। दशकों से इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डाला है, और यह बीमारी भौगोलिक अलगाव एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण और भी जटिल हो गई है। इस गंभीर आशयकता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। इस मौलिक पहल का उद्देश्य न केवल सिकल सेल के अनुवांशिक कारण का उन्मूलन करना है, बल्कि इस रोग से प्रभावित लाखों लोगों के सम्मान और अनुवांशिक को भी बहाल करना है।

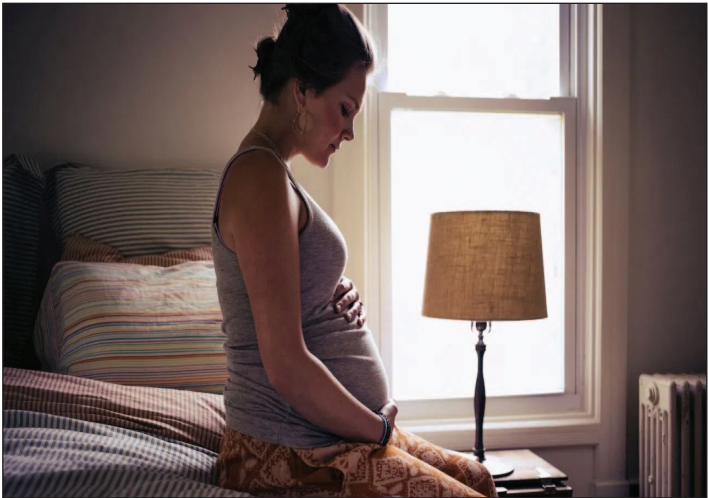
सिफल सेल गरो में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बढ़ा जाता है, जिससे उनकी आक्सीजन वहन क्षमता की क्षमता कम हो जाती है और धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ उत्पन्न होने लगती हैं। आइसलैंड्स जनसंख्या के बीच इसका प्रभाव विशेष रूप से उच्च है, क्योंकि वे इस आनुवंशिक बीमारी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वॉर्न ऑफ डिजीज एंस्टैट्स (2021) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 82,500 बच्चों का जन्म सिफल सेल रोग के साथ होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने इस संकेत से निपटने के लिए आधार तैयार किया और इसकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर जोर इसी के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023 में एनएससीआईएम की घोषणा की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 तक 40 वर्ष से कम आयु के 7 करोड़ व्यक्तियों की मिशन मोड में जाँच करने का लक्ष्य रखा गया। कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े जनसंख्या-आधारित आनुवंशिक जाँच कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2047 तक एससीडी के आनुवंशिक संरक्षण को समाप्त करना और पहले से ही इससे पीड़ित लोगों को व्यापक देखभाल प्रदान करना भी है। पहले दो वर्षों में, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इस मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। 31 जुलाई 2025 तक, 17 उच्च-व्यापकता वाले राज्यों के 300 से अधिक जिलों में 6.07 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। जांच किए गए व्यक्तियों में से 2.16 लाख रोगग्रस्त पाए गए, जबकि 16.92 लाख को वाहक के रूप में पहचाना गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 95% मामले केवल पाँच राज्यों—ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र—में केंद्रित हैं।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नवापारा की एक युवा आवासवासी लड़की मीना की कहानी इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक है। जांच अभियान के दौरान नैदानिक परीक्षण किए जाने पर, मीना को निम्न के एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में नामांकित किया गया। प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम और आशा कार्यकर्ता ने यह सुनिश्चित किया कि उरो-निःशुल्क हाइड्रोक्सीयूरिया औषधि समय पर मिलती रहे, जिससे सिकल सेल रोग के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी आई। आज, मीना पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और अपने समुदाय में आनुवंशिक रोग के परामर्श में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य निगरानी में तेजी लाने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुमोदित पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक उपकरण को लाया गया है। शुरूआत में इनकी संख्या केवल तीन तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 30 से अधिक हो गई है। इससे प्रति कित लागत ₹100 से घटकर ₹28 हो गई है। इस पहल ने एएससीडी के लिए लागत-प्रभाव और कुशल डायग्नोस्टिक क्षमताएं सुनिश्चित की हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन केवल स्क्रीनिंग पर केंद्रित नहीं है; यह एएससीडी से पीड़ित व्यक्तियों की समग्र देखभाल को भी प्राथमिकता देता है। मिशन के अंतर्गत प्रबंधन हस्तक्षेपों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ, आवश्यक दवाओं और निदान तक पहुँच शामिल है। सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए एक प्रमुख दवा, हाइड्रोक्सीयूरिया, को राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों सूची (इंडोएल) में शामिल किया गया है और अब यह आयुधामा आरोग्य मंदिर उप-स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, जिससे अंतिम व्यक्तिगत रूप से इसकी पहुँच सुनिश्चित होती है। यह मिशन सिकल सेल रोग के उन्मूलन की प्रमुख रणनीतियों के रूप में आनुवंशिक परामर्श और जन जागरूकता पर भी जोर देता है। अब तक 2.62 करोड़ से अधिक आनुवंशिक स्ट्रेट्स स्कैन का चुके हैं, जिससे लोगों को उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त हुई है।

अजब-गजब

ना जाना पड़े जेल इसलिए महिला
ने किया खेल, 4 सालों में 3 बार हो
गई गर्भवती, ऐसे हुआ खुलासा



प्रेमनिसे एक ऐसा दौर है, जिसमें मॉलियाओं को खास देखभाल की जरूरत होती है। जिस कारण कई देशों में इसको लेकर अलग-अलग कानून भी बनाए गए हैं। अक्सर डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा को जन्म देने की तुल्य पिछली और आगामी प्रेगनेसी में 18 से 24 महीनों का अंतर होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग होते हैं, जो इन बातों को दरकिनारा करके सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा और 4 सालों में तीन बच्चों को भी बना गए। ये कहानी जब लोगों के बीच साजसे आई तो हर कोने में हैरान रह गया।

मामला चीन के शांशी प्रांत का है, जहाँ साल 2020 में बचें हांग नाम की महिला को 5 सालों के लिए जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो इस सजा बचने के लिए हर सा प्लेट होती रही। दरअसल, चीन के कानून के अनुसार यदि कोई महिला गलत हो या बच्चे को दूध पिला रही हो, तो उसे जेल में कैद करने के बजाय घर पर ही सजा काटने की अनुमति दी जाती है। चीन ने इसी का फायदा उठाया और हर बार सजा से बचने के लिए गर्भवती हो जाया करती थीं। जिससे वो अपनी कैद को टाल सके।

मई में हुई एक नियमित जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन उसकी भाभी के नाम पर है। जिसका मतलब यह था कि कागजों पर बच्चा उसकी भाभी का था। इसके बाद जांच शुरू हुई और जेबन ने पाया कि वह तलाक़शुदा है। उसके पहले दो बच्चे उसके पूर्व पति के पास रहते हैं, जबकि तीसरे बच्चे को उसने अपने पुत्र पति की बहन को दे दिया।

ऐसे में अधिकारियों को संदेह हुआ कि चैन जोग जानबूझकर गंभवती होकर सजा से बचने का तरीका अपना रही है। इसके बाद सिफारिश की गई कि उसे अब जेल भेजा जाए, चूंकि उसकी पांच साल की सजा में केवल एक साल से भी कम समय बच गया है, इसलिए उसे सीधे जेल भेजने के बजाय एक हिरासत केंद्र में रखा गया, ताकि वह बाकी की सजा पूरी कर सके।

अधिकारियों ने उसके साथ बेवकूफ कानून को जानकारी दी और समझाया कि उसे अब कानूनी दायित्वों का पालन करना होगा चैन होंग का मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी एक महिला जैंग ने इसी तरह का तरीका अपनाया था। उसे 2005 में भ्रष्टाचार के लिए उप्रकैद की सजा हुई थी, लेकिन उसने दस साल में कुल 14 गंभीरारण का दावा किया, जिनमें से 13 सही पाए गए।

आरक्षण में क्रीमी लेयर पर राजनीतिक दलों की चुप्पी

योगेंद्र योगी

देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जिसे हर राजनीतिक दल लपकने को तैयार रहता है। राजनीतिक दलों को लगता है कि बहुआयामी विकास के मुद्दे के बजाए आरक्षण को पैसाई करके सत्ता पाना ज्यादा आसान है। इसके लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि अदालतों के निर्णयों के लिए चुनौती देने में पीछे नहीं रहते। नेताओं की दिलचस्पी आरक्षण को बढ़ाने में रहती है। आरक्षण की जरूरत है या नहीं, इस पर चर्चा तक करने से कतराते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आय सीमा से संबंधित को संसदीय समिति की आठवीं रिपोर्ट में आय सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है।

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आय सीमा को 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने संबंधी संशोधन 2017 में किया गया था। कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के नियमों के अनुसार, इस सीमा की समीक्षा हर तीन साल पर या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी की जानी चाहिए। भाषायां सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने कहा कि वर्तमान सीमा कम है, जिसके दायरे में ओबीसी का केवल एक छोटा सा हिस्सा आता है। उन्होंने कहा कि मद्रास प्रसिद्धि और निम्न आय वर्ग की बढ़ती आय के कारण इसमें वृद्धि करना समय की मांग है।

संभव है कि संसद में इस समिति की सिफारिश मानते हुए आय सीमा बढ़ा दी जाए। इस पर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐराज करे। राजनीतिक दलों में इतना साहस ही नहीं है कि आरक्षण की सीमा तय करने और उसके प्रभावों पर किसी तरह की चर्चा करें। इसके विपरीत आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा रहती है। यही वजह है कि जब-जब आरक्षण में क्रीमी की पहचान कर अलग करने की बात की जाती है, तब राजनीतिक दलों को काट मार जाता है। क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा से सभी राजनीतिक दल भयभीत रहते हैं कि कहीं उनका वोट खिसक नहीं जाए। आरक्षित वर्ग के हित में होने के बावजूद कोई भी राजनीतिक दल क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करना तो दूर, बल्कि इस पर सार्वजनिक तौर पर बहस तक करने को तैयार नहीं है। जबकि यदि क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे आरक्षण से बाहर कर दिया जाए तो आरक्षण से वंचित उसी वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।

संसदीय समिति की जो रिपोर्ट संसद में रखी



हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्गों को आय सीमा बढ़ाने की सफाई तो गई है किन्तु क्रीमी वर्गों का जिक्र तक नहीं किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के पुनर्विचार पत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जर्मनी राज्य को आरक्षण के संदर्भ में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) जैसे आरक्षित श्रेणी समूहों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एसटी-एसटी क्रीमीलेयर को लेकर रिवीजन में कंटेनरी बनाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में कहा गया कि क्रीमी लेयर सिद्धांत, जो पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर लागू होता था (जैसा कि दूध साबनी मामले में उजागर होना चाहिए)। इसका मतलब है कि राज्यों को एससी और एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। उसे आरक्षण के लाभ से बाहर करना। अदालत ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि परिवार में क्रीमी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और

राज्य दर्जा प्राप्त कर लिया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। इस अन्याय में विभिन्न राज्यों के कानूनों को बरकरार रखना गया, जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था, जैसे कि के पंजाब और तमिलनाडु के कानून, जो श्रेणियों को अपसंसी और एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनासने की अनुमति देते हैं। अर्थात राज्य मौजूदा आरक्षण के दायरे में ही अति पिछड़ों की हच पर चर कर उसे अलग से आरक्षण दे सकते हैं। इस पथन राज्य्यादातर राज्य खोमोश है। उन्हें लगता है इससे जेस वगं का आरक्षण कम हुआ है, वह नाराज नहीं जा जाएगा और वो नहीं रोए। ऐसा करने से कहीं जेस वगं का वोटर बैक हाथ से नहीं हिसक जाए। यही वजह है कि सुप्रिम कोर्ट के निर्णय को एक

साल होने के बाद भी ज्यादातर राज्यों ने आरक्षित
दायरे में अति पिछड़ों की पहचान कर उन्हें अलग
से आरक्षण देने की कवायद तक नहीं की।

क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर देश के किसी भी राजनीतिक दल और सरकारों ने चर्चा तक नहीं की। जबकि कोर्ट का साफ कहना था कि क्रीमी लेयर को हटाने से उसी वर्ग के वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। राजनीतिक दलों ने पहले कभी ओबीसी के क्रीमी लेयर का जिक्र तक नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एएससी-एस्टी को भी शामिल कर लिया। यह मुद्दा नेताओं के लिए अव्यधिक ज्वननशील हो गया। क्रीमी लेयर को हटाना तो दूर रहा कोई इसके दायरे पर बहस तक करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत राजनीतिक दल आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने पर तत्पर हैं।

नेताओं को लगता है कि आक्षेपण की सीमा में नाए वगैरों को शामिल करने से उनका वोट बैंक मजबूत होगा। यह अलग बात है कि आक्षेपण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने के उनके मंसूलों को सुप्रीम कोर्ट ने सफल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 30 प्रतिशत को यह घोषणा की थी कि आगामी जनगणना के साथ-साथ जाति गणना भी की जाएगी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने की अपनी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने कहा, 'रैजिस्ट्रेशन पर 50 प्रतिशत की सीमा हमारे देश की प्रगति और पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासियों की प्रगति में बाधा बन रही है और हम चाहते हैं कि इस बाधा को समाप्त किया जाए।'

गौतमलव है कि सुप्रोम कोर्ट ने भी 50 प्रतिशत कोटा सीमा का हवाला देते हुए आरक्षण के प्रयासों को खारिज कर चुका है। आरक्षण का दायरा बढ़ाया कि पैरवी करने वाले राहुल गांधी ने एक बार भी क्रीमी लेयर को हटाने की बात नहीं कही। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को लगता है कि आरक्षण को दायरा बढ़ा कर वोट बैंक बढ़ाना ज्यादा आसान है। इसके विपरीत देश में विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। यही वजह है राजनीतिक दल आरक्षण का कड़े पीढियों से लगातार फायदा ले चुके वर्ग को भी आरक्षण के दायरे से बाहर करने से कतराते रहे हैं। देश का दूसरे दूसरे आर्थिक वर्ग का हिस्सा हड़पा जाता रहे।

ब्लॉग

उपराष्ट्रपति चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की सियासी लड़ाई बनाने के रणनीतिक मायने

कमलेश पांडे

उपराष्ट्रपति पद के लिए अब एनडीए और इंडिया ब्लाक दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने जहाँ महापुरुष के राज्यात्मक प्रतीक राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं उससे मुकाबले के लिए इंडिया ब्लाक ने सुभाष कोर्ट के रिटायर्ड जज बी. सुदर्शन रेड्डी को चुना। सुभाष मैदान में उतरा है। इस प्रकार एक तरफ जहाँ मोदी ने एनडीए उम्मीदवार की तारीफ करते हुए कहा है कि राधाकृष्णन सियासी खेल नहीं करते हैं, बल्कि सुलझे हुए राजनेता हैं। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष ने इंडिया ब्लाक के उम्मीदवार रेड्डी को गैरराजनीतिक चेहरा बताते हुए कहा है कि मौजूदा चुनाव विचारधारा (संघ बनाम प्रांतीयशील) की चुनौती है। साधारण (संघ) में कहे तो उपराष्ट्रपति चुनना ही राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षता की चुनौती लड़ाई का ऐसा अखाड़ा बना दिया गया है, जिसके रणनीतिक मायने भी दिलचस्प हैं।

यूँ तो संख्या बल में एनडीए यानी सत्ता पक्ष का प्रतीक भारी है, लेकिन वह लड़ाई आंकड़ों से तो अत्यन्तदा प्रतीकवादी प्रकृत होती है। देखे जाएँ तो अपने-अपने सिपायी अहम के सवाल पर विभाजित रहें। विपक्ष में भी पुनः एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक मजबूत प्रत्याशी उतारकर सत्ता पक्ष को यहाँ देश के विकास के का प्रयास किया है कि वह किसी मोह पर सरकार को फ्री हैट नहीं देने जा रहा है। उसके सत्ता के कदम से विपक्ष को फायदा भी जा न हो, लेकिन एनडीए में शामिल दलों की पूछ परख बड़ जाएँ। वहाँ, किसी भी सहयोगी ने यह थोड़ा सा धात कर दिया तो फिर सत्ता पक्ष की किरकरी भी हो सकती है। यही वह है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति मुनव्वर हुसैन की दृष्टिगत कतिपय सवाल खड़े हो रहे हैं— खासकर उन जिस तरह से दोनों केंद्रीय सिपायी गठबंधनों ने अपने-अपने उम्मीदवार के नाम दिखाने भाग से प्रारंभ है, उससे भी उत्तर भारत के राजनीति ओर यह उल्लेखनीय है कि सर्वसम्मति से एनडीए का कैडेट बर्न राधेगुणपति तमिलनाडु से आते हैं। जबकि सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना (पुराने आंध्रप्रदेश) से हैं। सिद्धान्त, दोनों चेहरों का दिखाने भारत से होना महज सिपायी संयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे दोनों प्रतिस्पर्धी राजनीतिक गठबंधनों की कोई सुनिश्चित राजनीतिक योजना है और इसी वजह से यह हुआ कि अजय का अंधका दिलचस्प हो जाता है। दूसरा, विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार सत्ता राधाकृष्णन और इंदिरा ब्लॉक उम्मीदवार रेड्डी की लड़ाई को विचारधारा यानी धर्मनिरपेक्षता के लड़ाई बता रहे हैं। क्योंकि उनका कर्ना है कि जब एनडीए संघ के आदमी पर भरोसा कर रहा है तो वो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा यानी धर्मनिरपेक्षता से उम्मीदवार को सामने रख रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गठबंधन के



सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंच से एक संक्षिप्त से नोट पढ़कर इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रेड्डी के नाम का ऐलान किया, वह खासा अहम है।

जैसा कि खरगो ने कहा है कि सभी दलों ने सर्वसम्मति से रेड्डी की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। यह विपक्षी एकता के लिहाज से लोकतंत्र के लिए एक बड़ा क्षण है। लिहाजा, उन्होंने रेड्डी को राजनीतिक न्याय का चैंपियन करार दिया। जबकि मंच से ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद डरेक अ. ब्राउन ने कहा कि इस फैसले में आम आदमी पार्टी भी ब्लॉक के साथ है। बताया गया है कि इंडियन ब्लॉक के अंदर सभी दलों के साथ इस मामले पर एक सोमवार और मंगलवार सुबह अनौपचारिक बातचीत हुई थी।

दरअसल, इस पूरी प्रक्रिया में चार-पाँच नामों को लेकर सोमवार को चर्चा भी हुई, पर वह किताब ना किसी वजह से पूरे मापदंड पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। इसी दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व निदेशक और तमिलनाडु से आने वाले माइल स्वामी अन्नादुरई और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने सहमति पर चर्चा की। जवन दिन अरम नाम से भी आम सहमति नहीं बन पाई, तब मंगलवार दोपहर को खरों की ओर से सभी घटकों के नेतृाईदों के सामने रेड्डी को नाम रखने खाया, जिस पर किसी की ओर से आपत्ति नहीं जताई गई। बताया जाता है कि रेड्डी का नाम कांग्रेस शासित तेलंगाना की सोशल इंजीनियरिंग से भी जुड़ा रहा है। वहाँ की सरकार ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण के डेटा के विश्लेषण के लिए जिस पैन्ल का गठन किया था, उसका अगुआई रेड्डी ने ही की है। वहीं, टीएमसी जैसे दल की ओर से यह साफ कर दिया गया था कि इंडियन ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार में जो भी व्यक्ति सामने आए, वह गैर राजनीतिक हो। इसलिए रेड्डी के नाम पर आम सहमति बन गई।

बताया जाता है कि टीएमसी नेत्री व परिचय बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के नेता स्टालिन से कहा था कि चुनाव को तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु बनाने का अच्छा संकेत नहीं जाएगा। फिर बात आई कि बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को चुना जाए। इस पर कहा गया कि इसे बीजेपी दक्षिण में भुना लेगी। फिर छोटे राजनीतिक नाम से भी परहेज करने पर सहमति बनी। तब सबमें सहमति जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नाम पर हुई। इससे कांग्रेस को लगता है कि वह इस नाम को पेश कर आंध्र प्रदेश में भी अपनी साख जमा सकती है।

चूँकि, विपक्ष गठबंधन की दक्षिणी राज्यों के दलों पर भी नजर है। विपक्ष के एक नेता ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वाईआरसीपी अब अपने रुख पर फिर से विचार करेगा। बता दें कि वाईआरसीपी ने गत सोमवार को ही घोषणा की है कि वह उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन करेगा। इसे विपक्ष राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का काउंटर मान रहा है, जिसके जरिए एनडीए, डीएमके जैसे दलों को सोच में डालना चाहता है।

तीसरा, बीजपा नीत एनडीए के लिए दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाना अब भी मुश्किल भरा कार्य है। चूँकि कर्नाटक में उसकी जी-जमाई सिंघासी जैर्डी भी सूखती चली गई, इसलिए उसकी राजनीतिक मुश्किलों को समझा जा सकता है। जबकि विपक्ष की सिंघाससत के लिए दक्षिण भारत शुरू से ही एक ऐसा उर्वर राजनीतिक मैदान, रहा है, जहां से उसने भाजपा को संदेव मजबूत चुनौती पेश की है। इसलिए कहा जा सकता है कि जारी उपराष्ट्रपति चुनाव में इस पद के लिए घोषित उम्मीदवार रेड्डी पूर्व निर्धारित सिंघासी लड़ाई का विस्तारित रूप ही है।

खासकर जिस तरह से एनडीए सहयोगी टीडीपी ने इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान किया है, उसका प्रभावी असर

डेलॉय-फिक्की की रिपोर्ट : 2030 तक दोगुना होगा भारत का रिटेल बाजार, ई-कॉमर्स और घरेलू मांग बनेंगे विकास के इंजन

नई दिल्ली, एजेंसी। देश का खुदरा क्षेत्र 2030 तक दोगुना होकर 1.93 लाख करोड़ डॉलर का हो जाएगा। पांच साल की इस अवधि में यह क्षेत्र सालाना 10 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगा। 2024 में भारतीय खुदरा बाजार 1.06 लाख करोड़ डॉलर का था। डेलॉय एवं फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुदरा क्षेत्र के इस रफ्तार से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह देश का मजबूत घरेलू बाजार है। यह वैश्विक स्तर पर व्यापार में हो रहे भारी उतार-चढ़ाव से भारत को बचाने में मदद करता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत के खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है।

भारतीय कंपनियों ने छूट बढ़ने के बाद फिर शुरू की रूस से तेल की खरीदारी, चीन की आपूर्ति पर असर संभव

नई दिल्ली, एजेंसी। घरेलू सरकारी कंपनियों ने छूट बढ़ने के कारण रूस से फिर कच्चे तेल की खरीद शुरू कर दी है। भारत पेट्रोलियम व इंडियन ऑयल ने सितंबर और अक्तूबर डिलीवरी के लिए खरीद शुरू की है। पिछले कुछ समय से रूसी तेल पर छूट काफी कम हो गई थी, जिससे खरीद को रोक दिया गया था। सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों की ओर से रूसी तेल आयात फिर से शुरू करने से शीघ्र खरीदार चीन के लिए आपूर्ति कम हो सकती है। जब घरेलू कंपनियों ने खरीद रोक दी थी, तब चीन ने अपनी खरीद को बढ़ा लिया था। घरेलू रिफाइनरियों ने जुलाई में कम छूट और अमेरिका की ओर से आपूर्ति के बाद रूसी तेल की खरीद रोक दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद के एवज में 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगाने की भी धमकी दी थी।

अधिकारियों ने बताया, यूराल्स क्लूड पर छूट बढ़कर तीन डॉलर प्रति बैरल हो गई है। इससे यह तेल रिफाइनरियों के लिए आकर्षक हो

है। साथ ही, यह ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का आत्मविश्वास भी दे रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देश का डी2सी (डायरेक्ट-टु-कंज्यूमर) बाजार भी 2030 तक 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। 2024 में यह 80 अरब डॉलर का था। डेलॉय दक्षिण एशिया के पार्टनर एवं कंज्यूमर इंडस्ट्री लीडर आनंद रमणनाथन ने कहा, भारत में युवा और डिजिटल तकनीक जानकार आबादी, मध्य वर्ग की बढ़ती ताकत और छोटे शहरों का आर्थिक प्रभाव खुदरा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ई-कॉमर्स लेनदेन का 60 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इन्हीं शहरों से आ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, युवा पीढ़ी की 250 अरब डॉलर की खर्च करने की क्षमता के साथ बढ़ती क्रय शक्ति से घरेलू मांग को बढ़ावा मिल रहा

है। रूसी तेल के 15 कागों खरीदे हैं।

छूट घटने से जुलाई में कम हो गई थी तेल की खरीदी

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत का रूसी तेल आयात कम हो गया था, क्योंकि कुछ रिफाइनरियों ने कम छूट के कारण खरीदारी धीमी कर दी थी। इसके अलावा, बारिश में भारतीय ईंधन की मांग भी आमतौर पर कम हो जाती है। हालांकि, रूसी तेल आयात अगस्त में और कम होने की संभावना है, क्योंकि भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने छूट कम होने के कारण यूराल क्लूड की खरीदारी रोक दी थी। भारत ने जुलाई में प्रतिदिन 15 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया जो जून की तुलना में 24.5 फीसदी कम है। जुलाई में भारत के कुल आयात (44.4 लाख बैरल प्रतिदिन) में रूस का योगदान 34 फीसदी था।

इस दौरान भारत का तेल आयात सितंबर, 2023 के बाद से सबसे कम रहा।

अनुसार, जुलाई से दिसंबर तक 88% कंपनियां नई भर्तियां करेगी, खासकर ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में । खुदरा और विनिर्माण क्षेत्र भी सक्रिय हैं । स्टार्टअप्स में फ्रेशर्स के लिए नौकरी के बेहतर अवसर बन रहे हैं, जो रोजगार बाजार को मजबूत कर रहे हैं ।



कहा, जैसे-जैसे उद्योग तकनीक के साथ विकसित होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञता को मानवीय कौशल के साथ मिलाने वाले नए लोग खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। हालांकि, समग्र फ्रेशर भर्ती की मंशा इस साल जनवरी-जून के दौरान 74 प्रतिशत से जुलाई-दिसंबर के लिए 70 प्रतिशत तक कम हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च विकास वाले क्षेत्रों में फ्रेशर्स के लिए अवसर मजबूत बने रहे। डिग्री प्राप्त प्रशिक्षुओं की मांग में लगातार वृद्धि देखी गई। इसमें विनिर्माण 37 प्रतिशत, इंजीनियरिंग-बुनियादी ढांचा 29 फीसदी और सूचना प्रौद्योगिकी 18 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहे।

प्रशिक्षुओं के लिए इन शहरों में मिलेंगे ज्यादा रोजगार के अवसर

बंगलूरु, चेन्नई और पुणे क्रमशः 37 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 26 प्रतिशत के साथ प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के इरादे से सबसे आगे हैं। बड़े उद्यमों की तुलना में छोटे संगठन भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति में मजबूत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति क्षमता

सीमित है।

एआई एजेंट से एशिया-प्रशांत की कंपनियों का 20% बढ़ेगा राजस्व

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एजेंट से एशिया-प्रशांत की कंपनियों का 20 फीसदी राजस्व बढ़ेगा। सेल्सफोर्स के एक सर्वे के मुताबिक, 75 फीसदी मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) का मानना ​​है कि इससे व्यावसायिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन आएगा।

सेल्सफोर्स का यह निष्कर्ष एआई रणनीति में बदलाव की उजागर करता है, जो सतर्क खर्च करने वालों से रणनीतिक निवेशकों की ओर बढ़ रहा है। एआई एजेंट रणनीतिक कार्यों को संभालकर लागत कम करते हैं और राजस्व को बढ़ाते हैं।

75 फीसदी सीएफओ ने कहा, एआई एजेंट लागत कम करके राजस्व भी बढ़ाएंगे। सर्वेक्षण में 63 फीसदी ने पांच साल पहले एआई रणनीति को रुढ़िवादी बताया था, जो आज सिर्फ 3 फीसदी रह गया है। सर्वे में वैश्विक स्तर पर 261 सीएफओ शामिल थे।

बैठक में देखते रह गए विदेश मंत्री इशाक डार, काबुल में पाकिस्तान के साथ खेल गया चीन



काबुल, एजेंसी। काबुल में बुधवार (20 अगस्त) को 90 दिन बाद अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक की। इस बैठक का मकसद तीनों देशों की आपसी हित को साधना था, लेकिन बैठक में चीन और अफगानिस्तान ने अपना काम तो कर लिया पर पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। काबुल की बैठक में न तो पाकिस्तान में आतंक कटौत पर अफगानिस्तान ने कोई आश्वासन दिया और न ही

उसके साथ कोई अलग से ट्रेड डील किया। पाकिस्तान की तरफ से बैठक में उप प्रधानमंत्री इशाक डार पहुंचे थे। डार के पास विदेश विभाग का भी जिम्मा है।

पाकिस्तान के साथ कैसे खेल गया चीन?

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के विदेश मंत्री के साथ ही त्रिस्तरीय वार्ता के लिए काबुल पहुंचे थे। इस त्रिस्तरीय वार्ता में तीनों देशों

के बीच आतंक, सुरक्षा और व्यापार को लेकर बात होनी थी। बात हुई थी, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान के बदले चीन को मिल गया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने जो संयुक्त बयान जारी किया, उसमें आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया गया। तीनों देशों का संयुक्त बयान कुछ इस प्रकार है- ‘काबुल की बैठक में अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने व्यापार, पारगमन, क्षेत्रीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।’

इस बयान के तुरंत बाद एक बयान और जारी किया गया। यह बयान काबुल की तरफ से जारी किया गया, जो चीन को लेकर था। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के

मुताबिक काबुल में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान ने चीन को सुरक्षा की गारंटी दी। अफगानिस्तान ने कहा कि हम आपको यह आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी धरती से आपके खिलाफ कोई भी गलत गतिविधियां प्रयोजित नहीं की जाएंगी। दिलचस्प बात है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया। उलटें जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने टीटीपी का जिक्र किया, तो अफगानिस्तान ने इस पर चुप्पी साध ली। बीबीसी उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का कहना था कि आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान की कार्रवाई काफी धीमी है। हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान टीटीपी पर कार्रवाई करेगी। वहीं इस मुद्दे पर अफगान ने

अपना पुराना स्टैंड (हमारे यहां टीटीपी है ही नहीं) को बरकरार रखा।

ट्रेड डील पर भी पाक को नहीं मिला तोहफा

एक तरफ जहां काबुल तक चीन के सीपीईसी के निर्माण पर सहमति बन गई। वहीं इस डील में पाकिस्तान को कोई तोहफा नहीं मिल पाया। अफगानिस्तान के एरियाना न्यूज के मुताबिक जुलाई 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के व्यापार में 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस त्रिस्तरीय बैठक में इसके बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई भी ट्रेड डील नहीं हुआ। चीन ने अपना हित साधकर त्रिस्तरीय बैठक को खत्म करा लिया।

पाकिस्तान बंद कर रहा कई हवाई मार्ग, क्या कोई है बड़ी प्लानिंग?

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान देशभर में कई अहम हवाई मार्गों को अस्थायी रूप से बंद करने का नोटम (NOTAM) भी जारी किया गया है। इस कदम से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान किसी बड़े मिसाइल परीक्षण या एयर-डिफेंस सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में अपनी अगिन-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जब भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम की सफलता का जश्न मनाया, तो पाकिस्तान का आसमान बंद करने का फैसला उसकी असुरक्षा और घबराहट भरी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।

सेंट्रल सेक्शन पर पाबंदी

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि 22 अगस्त 2025 को सुबह 00:00 बजे से 02:30 बजे (UTC) तक इस्लामाबाद और नियंत्रण रेखा



(LoC) के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। इस दौरान नागरिक हवाई यातायात को इन मार्गों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी।

साउदर्न सेक्शन में भी बंदिशें

दक्षिणी हिस्से में लाहौर से लेकर

रहिमयार खान, कराची और ग्वादर तक कई अहम हवाई मार्ग 26 अगस्त 2025 को 00:30 बजे (UTC) तक बंद रहेंगे। इस पाबंदी का असर भारत से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक और अरब सागर के ऊपर उड़ने वाले विमानों पर भी पड़ेगा सूत्रों

का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से उठाया गया यह कदम किसी संभावित मिसाइल परीक्षण या एयर-डिफेंस से जुड़े अभ्यास का हिस्सा हो सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर के समय भी लगी थी पाबंदी

रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से पाकिस्तान को दो महीने में करीब 4।10 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच यह नुकसान हुआ।

मतदाताओं को अपनी याचिका पर साइन करने के लिए लॉटरी का सहारा लिया था। जबकि इस लॉटरी को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतदाता ये पैसा जीत सकते हैं। केस दर्ज कराने वालों ने कहा कि साइन करने वाले मतदाताओं को नाम, पते, ईमेल और फ़ोन नंबर भी देने को कहा गया था।

मस्क ने दिया ये तर्क

याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए, मस्क ने कई ‘‘लाल निशान’’ बताए, जो इस बात का सबूत थे कि उन्होंने कोई अवैध लॉटरी नहीं चलाई थी। उन्होंने कहा कि इनमें यह बयान भी शामिल था कि 10 लाख डॉलर के प्राप्तकर्ता ‘‘पैसे कमाने के लिए’’ चुने गए थे। जस्टिस ने अन्य बयानों का हवाला दिया, जिनसे पता चलता है कि प्रतिवादी 10 लाख डॉलर ‘‘दे रहे’’ थे, और यह राशि ‘‘जीती’’ जा सकती थी।



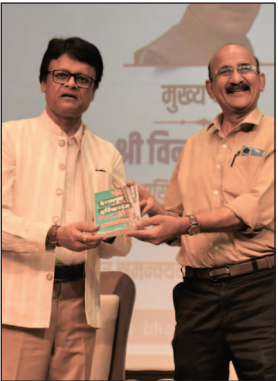
एमसीयू सत्रारंभ कार्यक्रम 'अभ्युदय' का दूसरा दिन

एआई से मीडिया में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी लेकिन गुणवत्ता में आएगा निखार : यशवंत व्यास

भोपाल। एआई एक अच्छा साथी या सेवक हो सकता है। इसका मुकाबला ईमानदारी जैसे गुणों से किया जा सकता है। एआई से घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंट मीडिया को एआई से बहुत फायदा होगा। एआई के इस दौर में हाइपर लोकल दुनिया बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भविष्य में प्रिंट मीडिया में फ़ीलड रिपोर्टिंग के जॉब्स बढ़ेंगे। उक्त बातें एमसीयू के सत्रारंभ कार्यक्रम 'अभ्युदय' के दूसरे दिन के पहले सत्र में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यशवंत व्यास ने कही। वे

बतौर मुख्य वक्ता 'एआई के दौर में प्रिंट मीडिया' विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।

एमसीयू के सत्रारंभ कार्यक्रम के दूसरे दिन आज विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ पत्रकार यशवंत व्यास, वरिष्ठ रेडियो उद्घोषक कमल शर्मा, जनसम्पर्क विशेषज्ञ डॉ. समीर कपूर, संस्कृतिधर्मी डॉ. सच्चिदानंद जोशी, पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं उद्घोषक विनय उपाध्याय के व्याख्यान हुए। प्रारंभिक



सत्र में बोलते हुए श्री यशवंत व्यास ने कहा कि आधुनिक तकनीक और मानव सभ्यता के विकास में इंटेलिजेंस कोसेंट, फिजिकल कोसेंट, इमोशनल कोसेंट और स्प्रिचुअल कोसेंट जैसे मानवीय गुणों के संदर्भों में कहा कि मशीनें या तकनीक मानव का मुकाबला नहीं कर सकतीं। यह बात जरूर है कि हमारे कई कामों जैसे कि श्रम वाले क्षेत्रों में तकनीक का दखल बढ़ा है। बहुत हद तक आईक्यू आधारित काम में भी इसका



समावेश बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी मानवीय गुण बहुत बुनियादी हैं और एआई जैसी तकनीकें इसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। प्रिंट मीडिया में इन्हीं मानवीय गुणों जैसी प्रीमियम वैल्यू पैदा करनी होंगी। सूचनाओं की दुनिया में मीडिया को विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। श्री व्यास ने एमसीयू में पत्रकारिता के इतिहास पर केंद्रित प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के ऐतिहासिक घटनाओं के कवरेज के प्रथम पन्नों की गैलरी की प्रशंसा भी की।

इस अवसर पर स्वागत भाषण में कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि पत्रकारिता खासकर प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता बहुत विशिष्ट रही है। बहुत से समाचार पत्रों और

पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में मानदंड स्थापित किए हैं। अपने पत्रकारीय जीवन के अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस तरह प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ने उनके लेखन में अहम भूमिका का निवाह किया है।

'आवाज की दुनिया' विषय पर अपने विचार रखते हुए प्रख्यात रेडियो उद्घोषक श्री कमल शर्मा ने कहा कि शब्द 'बम' का काम भी करते हैं और 'मरहम' का भी। अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा सुनना सीखिये। शब्द उदास भी करते हैं और शब्दों में वह ताकत भी होती है जो खुशी से भर दे। शब्द ब्रम्ह भी है जिसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अच्छी भाषा के साथ अच्छा बोलने का



संस्कार ही उद्घोषक को सफल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि शब्द की प्राण प्रतिष्ठा वाणी से ही होती है और वह प्रभावशाली हो जाता है। बोलते वक्त व्याकरण का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। उन्होंने ऑडियो मीडियम में आ रहे बदलावों सहित वाइस प्रोेक्शन, रेडियो के लिए लेखन आदि विषयों पर विस्तार से बात की। इसी सत्र में संवाद कौशल पर वरिष्ठ पत्रकार और कला समीक्षक श्री विनय उपाध्याय ने कहा कि संसार में भाषा के आने से पूर्व भी ध्वनियां मौजूद थीं। यही ध्वनि भाषा की मातृभूमि है और शब्द उसकी

पृष्ठभूमि। ज्ञान परंपरा का निर्माण वाचिक और शब्द जैसे अलग-अलग माध्यमों से हुआ है। शब्द के पास वाचिक शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि शब्द हमारी स्मृति में उठर जाते हैं। इसलिए अच्छा संवाद करने के लिए अच्छे संस्कार ही उद्घोषक को सफल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि शब्द की प्राण प्रतिष्ठा वाणी से ही होती है और वह प्रभावशाली हो जाता है। बोलते वक्त व्याकरण का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। उन्होंने ऑडियो मीडियम में आ रहे बदलावों सहित वाइस प्रोेक्शन, रेडियो के लिए लेखन आदि विषयों पर विस्तार से बात की। इसी सत्र में संवाद कौशल पर वरिष्ठ पत्रकार और कला समीक्षक श्री विनय उपाध्याय ने कहा कि संसार में भाषा के आने से पूर्व भी ध्वनियां मौजूद थीं। यही ध्वनि भाषा की मातृभूमि है और शब्द उसकी

जोशी ने कहा कि एक भारतीय बतौर हमारी पहली पहचान हमारी संस्कृति है। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा और संस्कृति बहुत समृद्ध है और यह पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। डॉ. जोशी ने कहा कि यह युग मोबाइल का नहीं बल्कि भारत का युग है। इसके बाद डिजिटल दौर में विज्ञापन और जनसंपर्क की रणनीतियों पर ब्रांड विशेषज्ञ डॉ. समीर कपूर ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल दौर में जनसंपर्क का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ है और इसमें अनेक नए आयाम जुड़े हैं। इस क्षेत्र में आने वालों को बाजार और बदलती तकनीकों, प्रतिस्पर्द्धा की बारीक जानकारीयां होना आवश्यक है। इन विविध सत्रों में पत्रकारिता विभाग के समाचार पत्र विकल्प, जनसंचार विभाग के पत्र 'पहल' का विमोचन भी हुआ। पत्रकारिता विभाग की छात्राओं सुश्री प्रज्ञा एवं सुश्री विशाखा को पंडित रामेश्वर दयाल स्मृति तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग में 2023-2025 में सबसे

अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रा सुश्री प्रतिष्ठा पवार को स्व. अम्बा प्रसाद स्मृति पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर पूर्व छात्राओं प्रियंका दूबे, सोनल पटेरिया, डॉ. शिवा श्रीवास्तव तथा रागेश्री गांगुली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विविध सत्रों का संचालन श्री लोकेन्द्र सिंह राजपूत, डॉ गरिमा पटेल, श्री विवेक सावरीकर, डॉ. संदीप भट्ट ने किया तथा आभार डॉ. राखी तिवारी विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, प्रो. संजय द्विवेदी, विभागाध्यक्ष जनसंचार विभाग, डॉ. आरती सारंग विभागाध्यक्ष पुस्तकालय विभाग तथा डॉ. पवित्र श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग ने किया। सत्रारंभ कार्यक्रम अभ्युदय के तीसरे दिन दिनांक 22 अगस्त 2025 को फिल्म समीक्षा विषय पर प्रख्यात पत्रकार श्री अनंत विजय का उद्घोधन होगा। सिनेमा लेखन के विविध आयाम विषय पर फिल्म निर्माता एवं लेखक विपुल रावल अपनी बात रखेंगे।

थामा का टीजर जारी, आयुष्मान-रश्मिका में दिखा रोमांस, मलाइका अरोड़ा ने लगाए ठुमके, जल्द रिलीज होगा ट्रेलर



स्त्री 2 के मेकर्स अपनी अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा से चर्चा में हैं। 15 अगस्त फिल्म की पहली झलक दिखाई थी और बीती 18 अगस्त को फिल्म से इसकी स्टार कास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल का फस्ट लुक सामने आया था। फिल्म की स्टार कास्ट का फस्ट लुक जारी करने के साथ-साथ मेकर्स ने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि वह फिल्म से सरप्राइज गिफ्ट देंगे और अपने वादे को पूरा करते हुए मेकर्स ने आज दर्शकों के लिए वो सरप्राइज शेयर कर दिया है।

1।49 मिनट के टीजर की शुरुआत रह पाओगी मेरे बिना सौ साल तक, 100 साल क्या एक पल भी नहीं रह पाऊंगी से होती और इसके बाद शुरू होता है, भूतिया खेल, में जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना एक भूतिया जंगल में फंसे नजर आ रहे हैं। इसके बाद परेश रावल की छोटी सी एंट्री होती है और फिर भूतिया जगहों का दीदार कराया जाता है, फिर आयुष्मान और रश्मिका के बीच रोमांस देखा जाता है, जिसे वैपायर बने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखते हैं, और कहते हैं, रुक क्यों गए, लगे रहो, मैंने 75

साल से रोमांस नहीं देखा है। मडोक फिल्म अपनी पहली लव-स्टोरी हॉरर फिल्म थामा से इस दिवाली धमाका करने आ रही है। इससे पहले फिल्म से सभी स्टारकास्ट के शानदार और इंटेस लुक वाले फर्स्ट लुक शेयर किए गये थे। इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल का फर्स्ट लुक सामने आया था। आयुष्मान और रश्मिका के फर्स्ट लुक की बात करें तो दोनों इंटेस लुक में दिखे थे। फिल्म में आयुष्मान का किरदार आलोक, रश्मिका का ताड़का रोशनी का होगा। परेश रावल को उनके फर्स्ट लुक में हैरान प्रेशान देखा जा रहा था। परेश रावल का रोल मिस्टर राम बजाज गोयल का है, जो हमेशा कॉमेडी में ट्रेजडी डूढ़ते हैं। वहीं, फिल्म के विलेन नवाज के वैपायर रोल का नाम यक्षासन है, जो अंधेरे का बादशाह है और उनका बड़े वाला लुक भी बेहद सस्पेंसिव था।

रिपोटर्स की मानें तो, फिल्म का दूसरा पार्ट भी बनेगा, जिसमें ना सिर्फ नवाजुद्दीन बल्कि आयुष्मान, रश्मिका और परेश रावल भी नजर आने वाले हैं। फिल्म में आयुष्मान एक इतिहास के जानकर बनेंगे और परेश रावल भूतिया स्टडी करने वाले बाबा। बता दें। स्त्री और भेड़िया की तरह रोशन शंकर ने ही फिल्म थामा का स्क्रीनप्ले किया है और साथ ही इसके डायलॉग भी लिखे हैं।

बागी 4 का पहला गाना गुजारा जारी, हरनाज संधू के साथ इश्क फरमाते दिखे टाइगर श्रॉफ

बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी बागी-4 का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया था। इसमें टाइगर श्रॉफ का खूंखार अवतार देखने को मिला था। अब इस फिल्म का पहला रोमांटिक गाना गुजारा रिलीज हो गया है।

इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ अपने प्यार की चाहत में जुनून की हद पार करते दिखेंगे। इस सिचुएशन को ध्यान में रख रोमांस से भरपूर गीत गढ़ा गया है। आज इसे टी-सीरीज के यूट्यूब अकाउंट पर रिलीज कर दिया गया। गुजारा में हमें टाइगर श्रॉफ के किरदार का रोमांटिक पहलू दिखाई देता है, जबकि ट्रेलर में हमें उनका एक्शन अवतार देखने को मिला था।

गाने में उनके साथ हरनाज संधू भी हैं। वो इस फिल्म में रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ की प्रेमिका के रोल में हैं। इस गाने में रॉनी अपने प्यार में खोया उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार दिखता है। यह गाना बताता है कि फिल्म में एक्शन की जगह एक प्यारी लव स्टोरी भी दिखाई देगी। कमेंट सेक्शन को देखने के बाद पता चल रहा है कि लोगों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। इसके बोल भी कमाल के हैं।

इसे जोश बरार और परंपरा ने गाया है। लिрикस जादीप और कुमार के हैं। गाने का संगीत सलामत अली मर्तोई और जोश बरार ने



दिया है। साजिद नाडियाडवाला ने कहानी और पटकथा लिखी है। ए. हर्ष इसके निर्देशक हैं। बागी 4 जबरदस्त एक्शन, धमाकेदार ड्रामा और अराजकता से भरी फिल्म होगी। बागी 4 आगामी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस गाने के सिंगर जोश बरार ने गाने के बारे

में बात करते हुए कहा, जब साजिद नाडियाडवाला सर और भूषण सर ने इस गाने की लिरिक्स सुनी, तभी कह दिया था कि ये गीत बागी-4 में होगा। जो भरोसा उन्होंने मुझ पर दिखाया उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूं। टाइगर श्रॉफ और हरनाज संधू ने इसमें जान डाल दी है, मैं लोगों का इसके प्रति रुझान देkhना चाहता हूं और इसे लेकर मैं काफी उत्सुक हूं।

सामंथा ने बताया क्यों कर रही कम काम, शारीरिक और मानिसक स्वास्थ्य को लेकर कही ये बात

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु पिछले कुछ वक़्त से काफी सीमित मात्रा में काम कर रही हैं। अब इसको लेकर अभिनेत्री ने खुलासा किया है और बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने खुद ये फैसला किया है।

सामंथा रुथ प्रभु की गिनती साउथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में होती है। अब वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी बन गई हैं और अपनी इस नई भूमिका को काफी एंजॉय भी कर रही हैं। हालांकि, उनका कहना है कि काम के बोझ को कम करने के लिए अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी, जो उन्हें दिल से पसंद होंगे। अब सिर्फ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं सामंथा

प्राजिया इंडिया के साथ बातचीत के दौरान सामंथा ने कहा कि अब वो क्वालिटी वर्क पर ध्यान देंगी और इसके लिए वो सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। इससे उनका वर्क लोड भी मैनेज रहेगा। एक्ट्रेस ने कहा, "मैं उस मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां मैं वो काम करती हूं जिनके लिए मैं पैशनेट हूं। इसमें फिटनेस और फिल्में दोनों शामिल हैं। मैं कई फिल्मों और सीरीज का हिस्सा रही हूं, लेकिन वो सभी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं थे, जिनको लेकर मैं काफी उत्साहित हूं या जिनको लेकर मैं पैशनेट हूं। लेकिन अब मैं जो भी काम करती हूं, जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूं, जिस भी फिल्म का निर्माण करती हूं, सबमें मेरा दिल बसता है।"

अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही एक्ट्रेस

अभिनेत्री का कहना है कि अब वो एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करती हैं। बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं और अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब एक साथ पांच फिल्में नहीं शूट करती। एक बात मुझे समझ आ गई है कि मुझे अपने शरीर की सुननी चाहिए, इसलिए मैंने काम कम कर दिया है। लेकिन

अब मैं जो भी करती हूं और जिसमें अपनी एनर्जी वेस्ट हूं, वह बहुत मायने रखता है। कोई भी काम बेवजह नहीं होता। प्रोजेक्ट्स की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन उनकी वो काम बेहतर है।

राज और डीके की सीरीज में नजर आएंगी सामंथा

वर्कफ्रंट की बात की जाए तो सामंथा ने हाल ही में बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली तेलुगु फिल्म 'शुभम' में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो राज और डीके द्वारा निर्मित सीरीज 'सिटाडेल: हनी बनी' में नजर आई थीं। वहीं आने वाले वक़्त में सामंथा राज और डीके की आगामी सीरीज 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' में दिखाई देंगी। इस शो में आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गव्वी और जयदीप अहलावत भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस सीरीज के साल 2026 में आने की उम्मीद है।

